

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5193
03.04.2023 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट की पहचान करने के लिए आकलन

5193. श्री अजय कुमार मंडल :
श्रीमती नवनित रवि राणा :
श्रीमती लॉकेट चटर्जी :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत दो वर्षों के दौरान सृजित ई-अपशिष्ट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त ई-अपशिष्ट संग्रहण के लिए अधिकृत एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): ई-अपशिष्ट के सृजन का आकलन, अधिसूचित इलैक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के विक्रय डाटा और औसत जीवन पर आधारित होता है। सृजित ई-अपशिष्ट का इनपुट डाटा केवल राष्ट्रीय स्तर पर समेकित किया जाता है। सीपीसीबी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 के तहत अधिसूचित इक्कीस (21) प्रकार के ईईई से देश में उत्पन्न ई-अपशिष्ट क्रमशः 13,46,496.31 टन और 16,01,155.36 टन अनुमानित था। देश में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 और उसमें किए गए संशोधनों के कार्य ढांचे के तहत ई-अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा है। नियमावली 1 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी है। नियमावली में निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है:

- प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, उपभोक्ता, थोक उपभोक्ता, संग्रहण केन्द्रों, डीलर्स, ई-रिटेलर, रिफर्निशर, भंजक और पुनर्चक्रक पर लागू हैं।
 - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था के तहत उत्पादकों को अपने ईपीआर के कार्यान्वयन के लिए सीपीसीबी से ईपीआर प्राधिकार प्राप्त करना होगा और अपने भंजकों/पुनर्चक्रकों के विवरण प्रस्तुत करने होंगे
 - अधिसूचित ईईई इक्कीस (21) प्रकार के हैं और उपर्युक्त नियमावली की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध हैं।
 - ईपीआर व्यवस्था के तहत अधिसूचित ईईई के उत्पादकों को पूर्व में बेचे गए ईईई से उत्पन्न और ईईई की बिक्री, जैसा भी मामला हो, के आधार पर वार्षिक ई-अपशिष्ट संग्रहण के लक्ष्य दिए गए हैं।
- (ii) मंत्रालय ने 2 नवंबर, 2022 को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2022 अधिसूचित की है। यह नियमावली 1 अप्रैल 2023 से ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली 2016 को प्रतिस्थापित करेगी। यह नियमावली ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए नई ईपीआर प्रणाली का प्रवर्तन करेगी। नई नियमावली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, रिफर्निशर, भंजक और पुनर्चक्रक पर लागू है।
 - सभी विनिर्माताओं, उत्पादक, रिफर्निशर और पुनर्चक्रकों के लिए सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अपेक्षित है।
 - कोई भी संस्था बिना पंजीकरण के कोई कार्य नहीं करेगी और न ही किसी अपंजीकृत संस्था के साथ कार्य व्यवहार करेगी।
 - अब प्राधिकार को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है और केवल विनिर्माता, उत्पादक, रिफर्निशर और पुनर्चक्रक के लिए पंजीकरण अपेक्षित है।
 - पर्यावरण क्षतिपूर्ति और सत्यापन और लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान लाए गए हैं।
- (iii) पूरे देश में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली 2016 के प्रवर्तन के लिए कार्य योजना मौजूद है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ई-अपशिष्ट कार्य योजना की स्थिति और प्रगति को अपलोड करने के लिए एक ई-अपशिष्ट प्रबंधन समीक्षा पोर्टल विकसित किया गया है।
- (घ): ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 के तहत ई-अपशिष्ट का संग्रहण प्राधिकृत भंजकों/पुनर्चक्रकों और उत्पादकों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर या अपने प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जा सकता है। देश में ई-अपशिष्ट के 567 प्राधिकृत भंजक/पुनर्चक्रक और 2300 प्राधिकृत उत्पादक हैं। प्राधिकृत भंजकों/पुनर्चक्रकों और उत्पादकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा अनुबंध-1 पर दिया गया है।

अनुबंध-1

प्राधिकृत भंजकों/पुनर्चक्रकों और उत्पादकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत भंजकों/पुनर्चक्रकों की संख्या	प्राधिकृत उत्पादकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10	10
2.	असम	01	03
3.	छत्तीसगढ़	02	06
4.	दिल्ली	06	633
5.	गुजरात	40	93
6.	गोवा	02	03
7.	हरियाणा	42	201
8.	हिमाचल प्रदेश	02	08
9.	जम्मू और कश्मीर	03	01
10.	झारखंड	02	01
11.	कर्नाटक	72	182
12.	केरल	01	62
13.	महाराष्ट्र	140	553
14.	मध्य प्रदेश	03	16
15.	ओडिशा	07	10
16.	पंजाब	08	12
17.	राजस्थान	27	27
18.	तमिलनाडु	42	136
19.	तेलंगाना	23	55
20.	उत्तर प्रदेश	121	191
21.	उत्तराखंड	08	09
22.	पश्चिम बंगाल	05	75
23.	चंडीगढ़	-	06
24.	मेघालय	-	01
25.	पुदुचेरी	-	01
26.	दमन और दीव	-	05
	कुल	567	2300